The ACHIEVERS IAS ACADEMY

ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Summary of the Hindu

06 March 2023

Medium HINDI

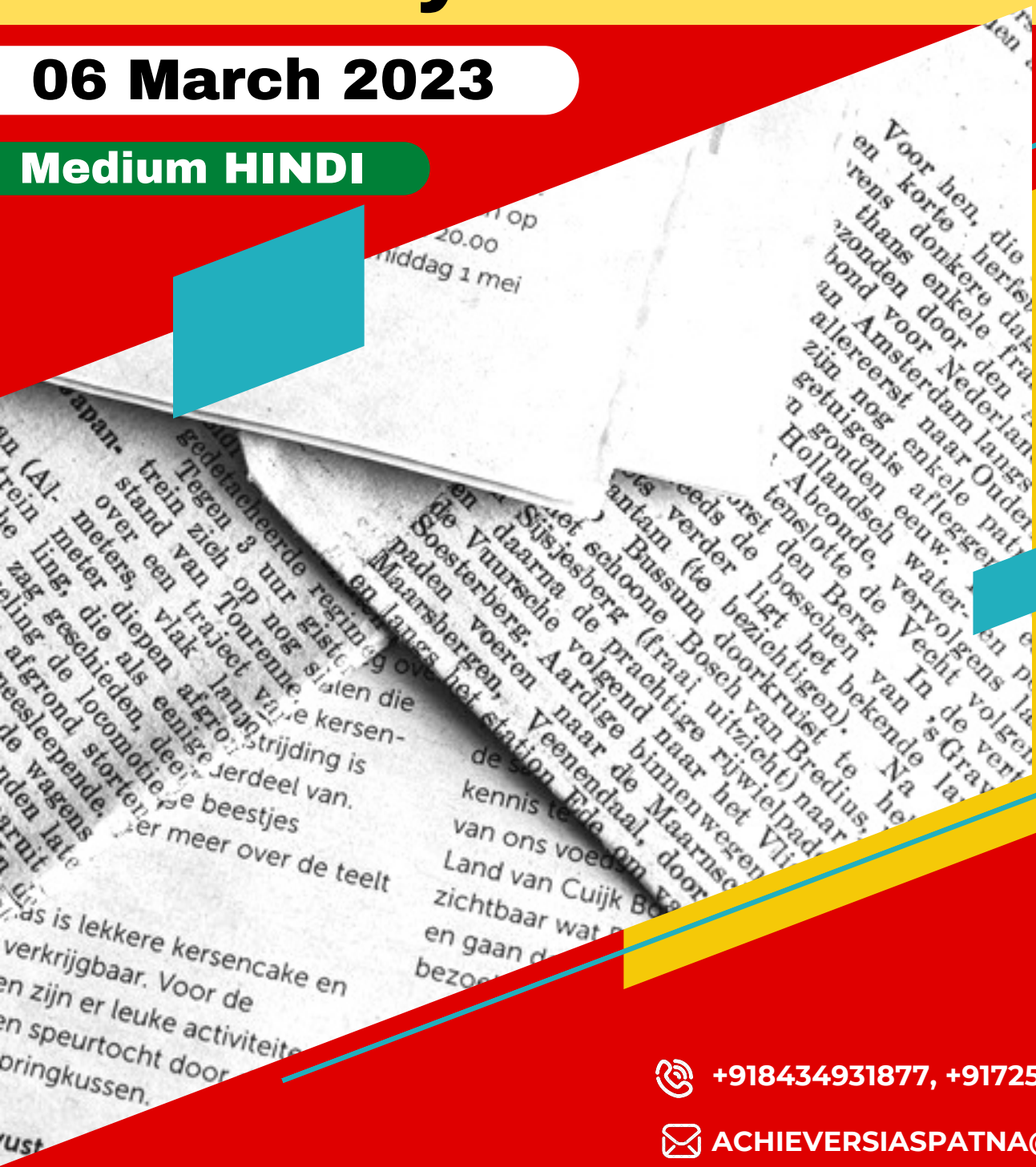

+918434931877, +917250667974

ACHIEVERSIASPATNA@GMAIL.COM

NEW PATLIPUTRA COLONY ROAD NO. 4A, NEAR TENNIS COURT, PATNA-13

WWW.ACHIEVERSIASPATNA.CO.IN

2023
CURRENT AFFAIRS

हिन्दू 06-03-2023 राष्ट्रीय

धीमी पुलिस सत्यापन कश्मीरी आकांक्षाओं को कुचल रहा है।

कई कश्मीरी निवासियों को लगता है कि पुलिस उन आवासों को दंडित करने के लिए वीज़ा निकासी प्रक्रिया में देरी कर रही है जिनके परिजनों का अलगाववादी झुकाव है। ऐसे लोग हैं जो पुलिस पर प्रतिकूल रिपोर्ट बनाने और इस प्रकार वीज़ा से इनकार करने का आरोप लगाते हैं। इसने बिना जोस और पासपोर्ट के सैकड़ों को छोड़ दिया है। महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इतिजा मुफ्ती जैसे कई जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं को 2022 में पासपोर्ट से वंचित कर दिया गया था।

आठ पार्टियों ने "राजनीतिक विच-हंट" के लिए एजेंसियों के उपयोग के खिलाफ पीएम को लिखा।

दिल्ली उप की पृष्ठभूमि के खिलाफ। सीबीआई द्वारा सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आठ राजनीतिक दलों ने ईडी और सीबीटी के दुरुपयोग के बारे में पीएम को लिखा है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के हस्ताक्षरकर्ता केसीआर, आप के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री। भागवत मान, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (टीएमसी), एनसीपी से शरद पवार, राजद के तेजस्वी यादव, सपा के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शामिल हैं। कांग्रेस का कोई हस्ताक्षरकर्ता इसमें नहीं है।

अडानी प्रोजेक्ट्स एक सरकार का सरकार के साथ डील की तरह है,

श्रीलंका एफएम का कहना है।
श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने द हिंदू के साथ एक साक्षात्कार में श्रीलंका में अडानी समूह की परियोजनाओं को "सरकार से सरकार" कहा है। इस तरह का सौदा "जैसा कि यह 'भारतीय सरकार थी जिसने उत्तरी श्रीलंका में पवन ऊर्जा परियोजना सहित पवन ऊर्जा परियोजना सहित बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए समूह की पहचान की थी।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अडानी पोस्ट, एयरपोर्ट और एनर्जी को लेकर आश्वस्त है। चूंकि इन कंपनियों के फंडामेंटल मजबूत हैं इसलिए श्रीलंकाई सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद अडानी के शेयरों में गिरावट के बारे में नहीं है।

तमिलनाडु भाजपा प्रमुख पर प्रवासी मजदूरों के राज्य पर "झूठा प्रचार" करने का मामला दर्ज किया गया चेन्नई पुलिस की अपराध शाखा ने सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले सोशल

मीडिया प्लेटफॉर्म पर "झूठे संदेश" पोस्ट करने के लिए भाजपा के टीएम प्रमुख के. अन्नादुरई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। के. अन्नादुराई ने ट्विटर पर ट्वीट और वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें डीएमके के मंत्रियों को उत्तर भारतीयों को "पानीपुरी वाला" कहते हुए देखा जा सकता है।
वर्तमान में तमिलनाडु में स्थानीय लोगों द्वारा उन पर हमला किए जाने की खबर से प्रवासी श्रमिक भयभीत हैं।

तमिलनाडु के राज्यपाल ने प्रवासी श्रमिकों से असुरक्षित महसूस न करने का आग्रह किया।

तमिलनाडु के राज्यपाल एन. रवि ने प्रवासी श्रमिकों को घबराने या असुरक्षित महसूस न करने के लिए कहा है, और राज्य के लोग मिलनसार और अच्छे हैं और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

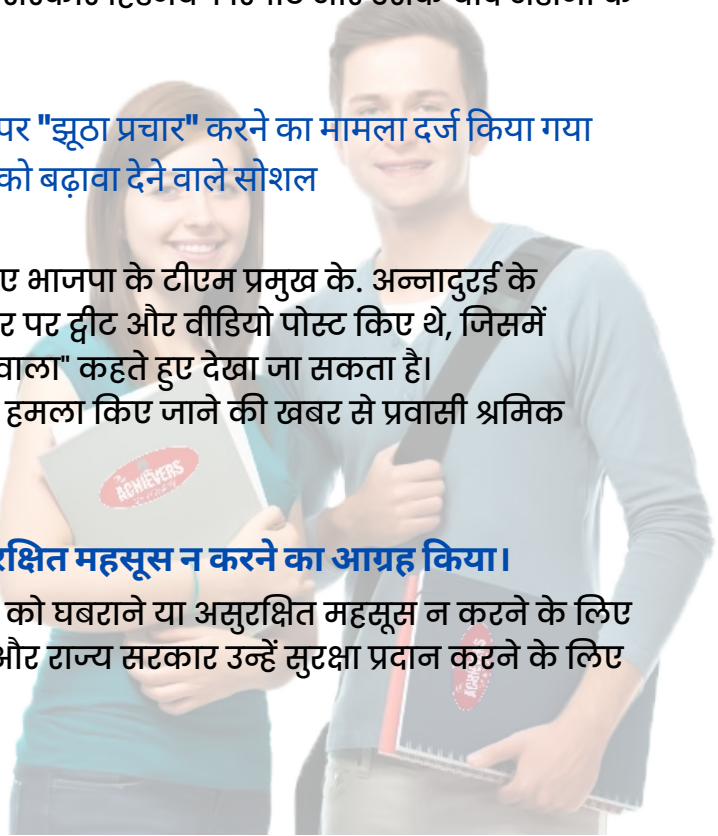

भारत में 'वैश्विक खुफिया प्रमुखों' का सम्मेलन

G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बीच भारत ने 1 मार्च को दुनिया भर के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे राइजिंग सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। इसमें 26 देशों की भागीदारी देखी गई।
सुरक्षा वार्ता बढ़ाना म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और शांगरी-ला संवाद, सिंगापुर की तर्ज पर है।
इसका आयोजन रिसर्च एंड एनालिसिस क्लिंग (RAW) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा किया जाता है। अमेरिका ने पस्त नहीं किया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ने इसमें भाग लिया। पीएम मोदी और अजीत डोवेल ने इसका उद्घाटन किया और इसमें काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग पर चर्चा की गई

इंडिया ने पोस्टरों को लेकर स्विस राजदूत को तलब किया।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (यूएनएचसीआर) कार्यालय के पास भारत के लिए महत्वपूर्ण पोस्टरों को लेकर भारत ने स्विस राजदूत को तलब किया।
MEA ने जेनिना (स्विट्जलैंड) में UNHCR अधिकारी के पास "निराधार और दुर्भाविनापूर्ण भारत विरोधी पोस्टरों का मुद्दा" उठाया।
संयुक्त राष्ट्र स्थापित और दुर्भाविनापूर्ण भारत विरोधी

इफको के नैनो डीएपी उर्वरक के लॉन्च को सरकार की मंजूरी।

सरकार। ने नैनो डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरकों के लॉन्च को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने इस बारे में एक ट्वीट में कहा, यह उर्वरक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इफको एक सहकारी कंपनी है जो उर्वरक बनाती है।

आरएसएस मीडिया विंग के सम्मेलन में संगठनों का कहना है कि धर्मांतरित लोगों के लिए कोई कोटा नहीं है।

धर्मांतरण और आरक्षण पर दो दिवसीय सम्मेलन के समापन पर आरएसएस के मीडिया विंग, विश्व संवाद केंद्र ने कहा कि उन्होंने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला है कि धर्मांतरितों को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
वे आदिवासियों, अनुसूचित जाति और अन्य हिंदुओं की ओर इशारा कर रहे थे जो मुस्लिम और ईसाई धर्म जैसे दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन धर्मांतरण के बाद भी वे आरक्षण की मांग करते हैं। एससी, एसटी आदि के तहत अन्य धर्मों में छुआछूत और जाति की अवधारणा है।

हाथरस मामले में 3 का बरी होना पुलिस द्वारा "ढीली" जांच दिखाता है: कांग्रेस।

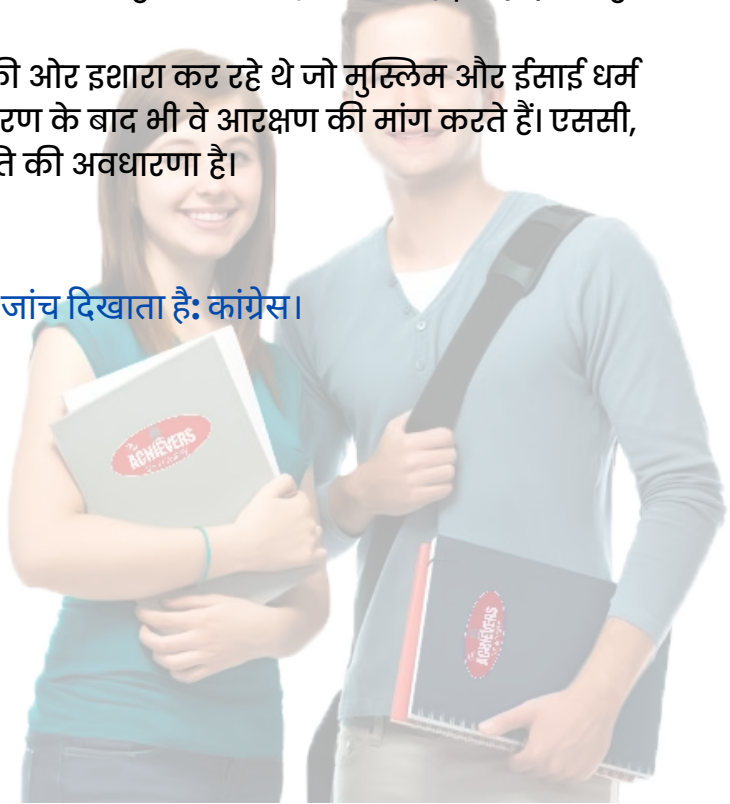

राज्य

➡ आप का कहना है कि सीबीआई सिसोदिया को झूठे आरोपों वाले कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रही है। कोर्ट ने सीबीआई की हिरासत **6** मार्च तक बढ़ा दी थी।
आप अपने नेताओं को चित्रित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि एक "राजनीतिक पीड़ित" के रूप में और यह बेहतर होगा कि वे अपने कुकर्मों के लिए जनता से माफी मांगें।

➡ रत्नागिरी में एक रैली में, महाराष्ट्र उदय ठाकरे ने कहा "शिंदे समूह को पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न देने का ईसीआई का कदम अस्वीकार्य है"। उन्होंने ईसीआई (भारत के चुनाव आयोग) पर सरकार से आदेश लेने का आरोप लगाया।

➡ केजरीवाल ने आप को विकल्प के रूप में पेश किया। रायपुर में छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्यों को खनन माफियाओं से छुटकारा दिलाने का वादा किया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर राज्य के शोध को लूटने का आरोप लगाया।

हिन्दू 06-03-2023 दुनिया

➡ **चीन ने रक्षा खर्च में7.2% की वृद्धि की।**

चीन सरकार। अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि करने की घोषणा की। 2023 में 225 बिलियन तक यह कहते हुए कि "जटिल सुरक्षा चुनौतियों" से निपटने के लिए वृद्धि की आवश्यकता थी, भारत का रक्षा बजट 72 बिलियन है

- नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) का वार्षिक सत्र चल रहा है जहां कई अन्य फैसले लिए गए 2023 के लिए चीन की आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 5% है।
- यह चीन का प्रीमियर ली केकिंग का पिछला एनपीसी सत्र था। ली कियांग होंगे चीन के नए प्रधानमंत्री

चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद केवल दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
पिछले साल चिन की अर्थव्यवस्था COVID से प्रभावित हुई थी।
एनपीसी - यह चीन की संसद है।

➡ **श्रीलंका के मछुआरे ने भारतीय मछुआरे को लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया।**

22 फरवरी को श्रीलंका के विदेश मंत्री ने संसद में कहा कि वे भारतीय मछुआरों को लाइसेंस देने की संभावना तलाश रहे हैं। लाइसेंस भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई जल में मछली पकड़ने की अनुमति देगा।
इस मुद्दे को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए उठाया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा, "2000 से 3000 [भारतीय ट्रॉलर] हर दिन हमारे समुद्र में आते हैं और हमारी नौसेना इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है।
हालांकि, श्रीलंकाई मातृ मछुआरे ने बताया है कि वे भारतीय मछुआरों को लाइसेंस देने की श्रीलंका सरकार की योजना का "घोर विरोध" करते हैं।
पाकिस्तान पुलिस इमरान खान को तोशखाना केयर में गिरफ्तार करने उनके घर लाहौर पहुंची, लेकिन खाली हाथ लौटी इमरान खान की कानूनी टीम ने पुलिस को आश्वासन दिया कि इमरान खान 7 मार्च को काउंट के सामने पेश होंगे। कोर्ट ने इमरान तोशखाना मामले में वारंट जारी किया है.

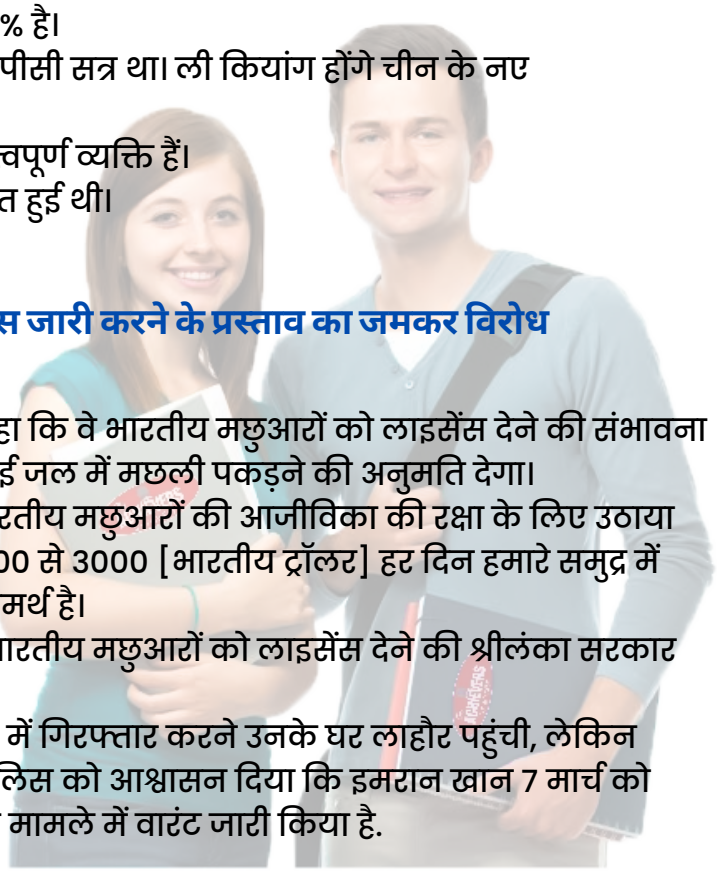

राष्ट्र गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए समझौता सुरक्षित करते हैं।

पहली बार, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक एकीकृत संधि पर सहमत हुए हैं
समुद्र के जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नया निकाय बनाया जाएगा।

उच्च समुद्र - खुला महासागर, किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं

यह वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है।
कर संक्रमण

जीएसटी राजस्व रुझान अधिक अनुपालन, आयात मांग में कमी का संकेत देते हैं

उच्चसमुद्र - खुलामहासागर, किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं

यह वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है।
कर संक्रमण

जीएसटी राजस्व रुझान अधिक अनुपालन, आयात मांग में कमी का संकेत देते हैं

संपादकीय

संपादकीय किस बारे में है?

संपादकीय महीनों में सरकार द्वारा जीएसटी संग्रह में वृद्धि के बारे में बात करता है। यह अपने नीतिगत परिवर्तनों के लिए सरकार की सराहना करता है जिसने बाद में GST कर संग्रह में वृद्धि की है, यह इससे संबंधित मुद्दों और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

जीएसटी संग्रह प्रवृत्ति कैसी है?

फरवरी, 2023 जीएसटी कलेक्शन 1-5 लाख करोड़ रहा। यह लगातार 12वां महीना है जिसमें जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ से ऊपर रहा है।
वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में औसत जीएसटी संग्रह 1,49,776 करोड़ रहा, जो कि (21.5% लाख करोड़) वित्त वर्ष - वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) है।

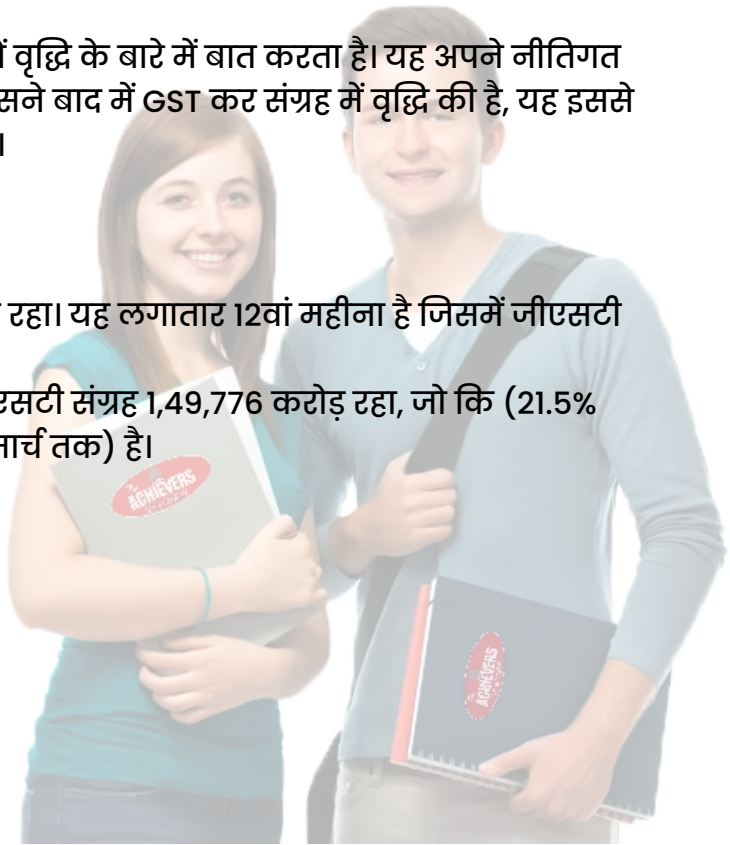

संपादकीय-1

बढ़ा हुआ GST संग्रह सरकार के यह कहने के साथ ठीक है कि हाल के वर्षों में नीतिगत परिवर्तनों से GST संग्रह में सुधार होगा।

जीएसटी संग्रह के संबंध में चिंताएं क्या हैं?

- वस्तुओंऔरसेवाओंकेआयातमेंवृद्धिहुईहै।मालके आयात से कर राजस्व में 29% की वृद्धि हुई है। सेवाओं के आयात से राजस्व में 22% की वृद्धि हुई है। यह डेटा वित्त वर्ष 23 के पहले 10 महीनों का है। आयात बढ़ना चिंता का विषय है, इससे कुछ रेवेन्यू मिलता है।
- घरेलू राजस्व रुझान असमान हैं ऐसे राज्य हैं जो काफी कम राजस्व संग्रह प्रदान करते हैं जबकि ऐसे राज्य हैं जो उच्च जीएसटी राजस्व देते हैं
- बजट 2023-24 में जीएसटी राजस्व वृद्धि को 22% से घटाकर 12% करने की बात कही गई है।

संपादकीय-2

ज्ञान पर प्रहार

गैर-सरकारी क्षेत्र को कानूनी पचड़े में नहीं घसीटा जाना चाहिए

संपादकीय किस बारे में है?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीपीआर (सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च) के लिए एफसीआरए पंजीकरण निलंबित कर दिया। संपादकीय सरकार की कार्रवाई पर भारी पड़ता है। इसमें कहा गया है कि सरकार बहुत असहिष्णु रही है और सीपीआर जैसे संगठन को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और यह प्रवृत्ति देश के अनुसंधान वातावरण के लिए अच्छी होगी।

सीपीआर क्या है और इसका पंजीकरण क्यों निलंबित किया गया?

सीपीआर - सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक थिंक टैंक है, जो सरकार के बारे में लेख, शोध पत्र प्रकाशित करता है। नीतियों, योजनाओं आदि के उल्लंघन के लिए एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) के तहत कर अनुपालन के लिए इसका एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, इसके बाद सीपीआर विदेशी संगठनों, व्यक्तियों से धन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।
सीपीआर में परिवर्तन हैं;

- निधियोंकाविपथन
- बीआईटी पेपर वर्क में चूक
- लेखा गणना में चूक

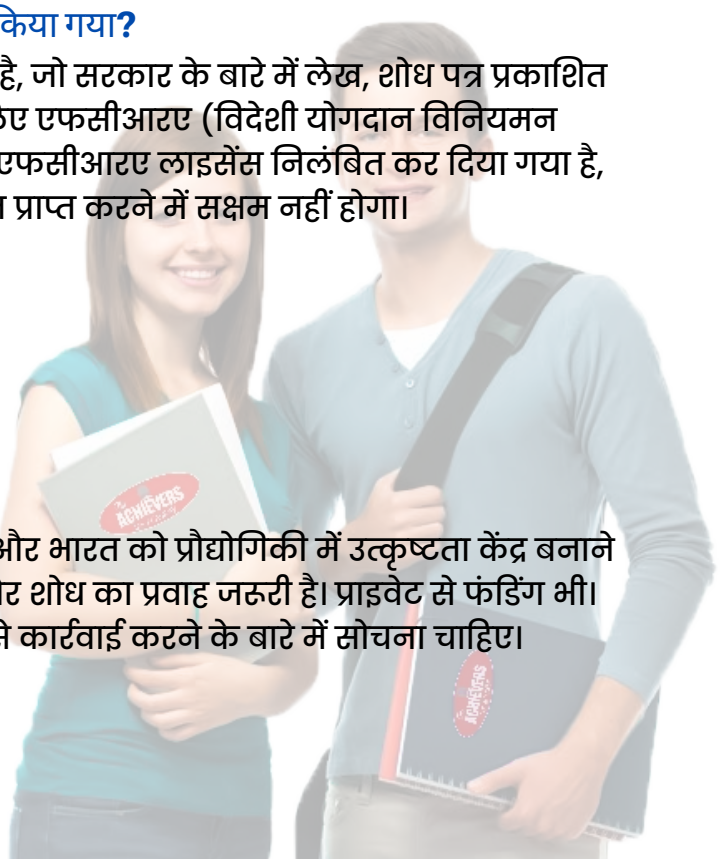

संपादकीय की चिंता क्या है?

भारत की नई शिक्षा नीति अनुसंधान को बढ़ावा देने और भारत को प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए दुनिया भर में ज्ञान और शोध का प्रवाह जरूरी है। प्राइवेट से फंडिंग भी। संगठन जरूरी भारत को हाल ही की तरह सावधानी से कार्रवाई करने के बारे में सोचना चाहिए।